RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 314
दि. 18.03.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

एक झटके में पूरी बिसात: ममता का मास्टरस्ट्रोक बंगाल चुनाव में मुकाबला हुआ सीधा और तीखा

जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है और इस बार खेल की शुरुआत ही बेहद आक्रामक अंदाज में हुई है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा दांव चला है, जिसने विपक्षी दलों को रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। पार्टी ने एक ही बार में 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जो न केवल संगठन की तैयारियों का संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि टीएमसी इस चुनाव को लेकर पूरी तरह आत्मविश्वास में है।

कोलकाता के कालीघाट स्थित आवास से उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया कि यह चुनाव केवल सत्ता बचाने का नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक विरासत को और मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी ने अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलन बनाने की कोशिश की है, ताकि हर क्षेत्र में मजबूत और प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। सूची में जहां कई पुराने और अनुभवी चेहरों को दोबारा मौका दिया गया है, वहीं कई नए चेहरों को भी मौका देकर पार्टी ने बदलाव का संकेत दिया है।

इस पूरी सूची में सबसे ज्यादा चर्चा भवानीपुर सीट को लेकर हो रही है। यह वही सीट है, जहां से ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ेंगी और यहां उनका संभावित मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से माना जा रहा है। यह मुकाबला केवल दो नेताओं के बीच नहीं, बल्कि दो राजनीतिक धाराओं के बीच सीधी टक्कर के रूप में देखा जा रहा है। भवानीपुर को ममता का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार चुनौती पहले से कहीं ज्यादा कठिन नजर आ रही है।

दरअसल, पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने दो सीटों—नंदीग्राम और भवानीपुर—से चुनाव लड़ा था। नंदीग्राम में उन्हें शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा था, जो कभी उनके करीबी सहयोगी रहे थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उस हार ने बंगाल की राजनीति को नया मोड़ दिया था और शुभेंदु को एक बड़े विपक्षी चेहरे के रूप में स्थापित किया था। हालांकि भवानीपुर से जीतकर ममता ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखी थी। इस बार जब वही दोनों चेहरे फिर आमने-सामने आने की संभावना है, तो यह मुकाबला प्रतीकात्मक रूप से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

टीएमसी की सूची पर नजर डालें तो साफ होता है कि पार्टी ने क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया है। उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक हर इलाके में स्थानीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। सिलिगुड़ी से गौतम देव, रायगंज से कृष्ण कल्याणी, सागरदिघी से बायरन बिस्वास और चोपड़ा से हामिदुल रहमान जैसे नेताओं को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा इस्लामपुर, हेमताबाद, बालुरघाट और हरिरामपुर जैसी सीटों पर भी मजबूत उम्मीदवार उतारे गए हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं।

उत्तर बंगाल, जिसे अक्सर चुनावी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, वहां भी टीएमसी ने इस बार पूरी तैयारी के साथ कदम रखा है। मालतीपुर, इंग्लिशबाजार, सुजापुर, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद जैसी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा यह दिखाती है कि पार्टी इस क्षेत्र में अपना जनाधार मजबूत करने के लिए गंभीर है। यह वही क्षेत्र है जहां विपक्ष, खासकर भाजपा, पिछले कुछ वर्षों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करती रही है।

उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका निभाने के बजाय भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है। उनका यह बयान चुनावी माहौल को और अधिक गर्माने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में चुनाव केवल विकास और नीतियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संस्थाओं की निष्पक्षता भी एक बड़ा मुद्दा बनेगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक साथ पूरी सूची जारी करना एक रणनीतिक कदम है। इससे पार्टी के भीतर किसी तरह की असमंजस या असंतोष की संभावना कम हो जाती है और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश जाता है कि संगठन पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुका है। साथ ही विपक्ष को भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा में तेजी लानी पड़ती है, जिससे उनकी रणनीति पर दबाव बनता है। इस चुनाव में सबसे दिलचस्प पहलू यह होगा कि क्या ममता बनर्जी अपनी लोकप्रियता और संगठनात्मक मजबूती के दम पर सत्ता में वापसी कर पाएंगी, या फिर भाजपा इस बार उनके गढ़ में सेंध लगाने में सफल होगी। भवानीपुर और नंदीग्राम जैसे सीटों पर होने वाला मुकाबला पूरे राज्य के चुनावी परिणामों की दिशा तय कर सकता है।

पश्चिम बंगाल का यह चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला भी माना जा रहा है। ऐसे में हर छोटी-बड़ी रणनीति का महत्व बढ़ जाता है। टीएमसी द्वारा एक साथ 291 उम्मीदवारों की घोषणा ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी इस बार कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है और हर मोर्चे पर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है।

आने वाले दिनों में जैसे-जैसे अन्य दल अपने पत्ते खोलेंगे, चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प होता जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि ममता बनर्जी ने शुरुआती चाल में ही ऐसा दांव चला है, जिसने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह गर्मा दिया है और मुकाबले को सीधा, तीखा और बेहद रोमांचक बना दिया है।

चुनावी महासंग्राम की तैयारी तेज: 1111 पर्यवेक्षकों की तैनाती से सख्त निगरानी का संकेत

जीएनएस)। नई दिल्ली। देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी हैं। राजनीतिक दल जहां अपनी-अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने भी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने घोषणा की है कि आगामी चुनावों और उपचुनावों के मद्देनजर कुल 1,111 पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर्स) की तैनाती की गई है, जो पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान निगरानी की अहम जिम्मेदारी संभालेंगे।

यह पर्यवेक्षक ऐसे समय में तैनात किए गए हैं, जब चुनावी माहौल तेजी से गरमाता जा रहा है और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। आयोग का यह कदम इस बात का संकेत है कि वह किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी को लेकर सतर्क है और चुनावों को पूरी तरह निष्पक्ष बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

इन चुनावों में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान होना है, उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं। इसके अलावा अप्रैल महीने में कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव भी कराए जाएंगे, जिससे चुनावी गतिविधियां और भी व्यापक हो जाएंगी। ऐसे में आयोग द्वारा बड़ी संख्या में पर्यवेक्षकों की तैनाती चुनाव प्रक्रिया की गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाती है।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, ये सभी पर्यवेक्षक चुनाव के दौरान 'आंख और कान' के रूप में कार्य करेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदान प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। इसके लिए उन्हें विशेष अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं, ताकि वे किसी भी शिकायत या अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई कर सकें।

आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी पर्यवेक्षक निर्धारित समय सीमा के भीतर, यानी गुरुवार तक, अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर कार्यभार संभाल लें। वहां पहुंचने के बाद वे अपने संपर्क विवरण सार्वजनिक करेंगे, जिससे उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और आम नागरिकों को सीधे उनसे संपर्क करने में सुविधा हो सके। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि चुनाव से जुड़ी शिकायतों और सुझावों का तुरंत समाधान हो सके और पारदर्शिता बनी रहे।

पर्यवेक्षकों की भूमिका केवल निगरानी तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे चुनावी प्रक्रिया के हर चरण पर नजर रखते हैं—चाहे वह नामांकन हो, प्रचार हो, मतदान हो या मतगणना। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि आचार संहिता का पालन हो रहा है या नहीं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, और कहीं मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। इस तरह उनकी मौजूदगी चुनावी प्रक्रिया में विश्वास और पारदर्शिता को मजबूत करती है।

चुनाव आयोग द्वारा 15 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से ही सभी राज्यों में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा, जबकि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में बहु-चरणीय मतदान का फैसला वहां की भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर पर्यवेक्षकों की तैनाती से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और मतदाताओं का भरोसा मजबूत होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या विवाद को समय रहते सुलझाया जा सके। यह कदम उन आरोपों को भी कम करने में मदद कर सकता है, जो अक्सर चुनावों के दौरान निष्पक्षता को लेकर उठते रहते हैं।

चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं होते, बल्कि यह लोकतंत्र की मजबूती का सबसे बड़ा प्रतीक भी हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाए रखे। 1,111 पर्यवेक्षकों की तैनाती इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

अब जैसे-जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी, राजनीतिक गतिविधियां और तेज होंगी, रैलियों और प्रचार का दौर चरम पर पहुंचेगा और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी बढ़ेगा। ऐसे में पर्यवेक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। उनकी सतर्क निगरानी यह तय करेगी कि चुनाव केवल प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी उदाहरण बन सके।

संसद की गरिमा पर विवाद: 204 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने राहुल गांधी से मांगी सार्वजनिक माफी

जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की राजनीति में एक नया विवाद उस समय उभर कर सामने आया, जब राहुल गांधी के संसद परिसर में किए गए प्रदर्शन को लेकर 204 पूर्व सैन्य अधिकारियों, रिटायर्ड राजनयिकों और वरिष्ठ वकीलों ने कड़ी नाराजगी जताई। इन सभी गणमान्य व्यक्तियों ने एक संयुक्त पत्र जारी कर न केवल उनके व्यवहार की आलोचना की, बल्कि उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की है। यह घटनाक्रम संसद की गरिमा, लोकतांत्रिक परंपराओं और राजनीतिक आचरण को लेकर एक नई बहस को जन्म दे रहा है। पूरा मामला 12 मार्च 2026 का है, जब राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन उस समय हुआ, जब पहले से ही संसद परिसर में धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाई गई थी। पूर्व अधिकारियों का कहना है कि ऐसे में यह कदम नियमों की स्पष्ट अवहेलना को दर्शाता है। उनके अनुसार, जब नियम पहले से निर्धारित हों, तो जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनका पालन करें और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखें। इस पूरे विवाद का सबसे चर्चित पहलू वह दृश्य रहा, जिसमें विपक्षी सांसद संसद की सीढ़ियों पर बैठकर 'चाय-बिस्किट' के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। इस पर आपत्ति जताते हुए पूर्व सैन्य अधिकारियों ने कहा कि संसद कोई सामान्य सार्वजनिक स्थल नहीं है, बल्कि यह देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है। ऐसे में वहां इस तरह का व्यवहार उसकी गरिमा के अनुरूप नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार, यह प्रदर्शन एक गंभीर राजनीतिक मुद्दे के बजाय एक प्रतीकात्मक नाटकीयता जैसा प्रतीत हुआ, जिससे संस्था की छवि प्रभावित होती है। संयुक्त पत्र में यह भी कहा गया है कि संसद को अक्सर 'लोकतंत्र का मंदिर' कहा जाता है और इस दृष्टि से उसकी पवित्रता केवल सदन के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे परिसर में बनी रहनी चाहिए। पूर्व अधिकारियों का मानना है कि संसद की सीढ़ियां, गलियारे और अन्य स्थान भी उसी सम्मान के पात्र हैं, जैसे कि सदन के भीतर का वातावरण। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यक्तिगत या दलगत राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो एक खतरनाक प्रवृत्ति है।

इस मुद्दे को और गंभीर बनाते हुए पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया कि राहुल गांधी वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में उनके आचरण का प्रभाव केवल उनके दल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पूरे विपक्ष और व्यापक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्व अधिकारियों का कहना है कि इस पद पर रहते हुए उनका व्यवहार अनुकरणीय होना चाहिए, ताकि जनता के बीच सकारात्मक संदेश जाए।

पत्र में यह चिंता भी व्यक्त की गई है कि संसद में बार-बार होने वाले हंगामों और प्रदर्शनों के कारण जनता का समय और संसाधन दोनों प्रभावित होते हैं। संसद की कार्यवाही बाधित होने से महत्वपूर्ण विधायी कार्य रुक जाते हैं, जिससे शासन व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इसे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बताया और कहा कि राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।

अंततः, इन 204 गणमान्य व्यक्तियों ने राहुल गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की अपील की है। उनका कहना है कि यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की जिम्मेदारी है कि वे संसद की गरिमा को बनाए रखें और उसे राजनीतिक टकराव का मंच बनाने से बचें। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण पहले से ही बढ़ा हुआ है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं न केवल राजनीतिक तनाव को बढ़ाती हैं, बल्कि आम जनता के बीच भी लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर भ्रम और अविश्वास पैदा कर सकती हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राहुल गांधी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या यह विवाद किसी बड़े राजनीतिक विमर्श का रूप लेता है या समय के साथ शांत हो जाता है।

दो दशक की निष्ठा के बाद बड़ा मोड़: केसी त्यागी का जेडीयू से अलग होना, सियासत में नए समीकरणों के संकेत

जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की राजनीति में एक नया विवाद उस समय उभर कर सामने आया, जब राहुल गांधी के संसद परिसर में किए गए प्रदर्शन को लेकर 204 पूर्व सैन्य अधिकारियों, रिटायर्ड राजनयिकों और वरिष्ठ वकीलों ने कड़ी नाराजगी जताई। इन सभी गणमान्य व्यक्तियों ने एक संयुक्त पत्र जारी कर न केवल उनके व्यवहार की आलोचना की, बल्कि उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की है। यह घटनाक्रम संसद की गरिमा, लोकतांत्रिक परंपराओं और राजनीतिक आचरण को लेकर एक नई बहस को जन्म दे रहा है। पूरा मामला 12 मार्च 2026 का है, जब राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन उस समय हुआ, जब पहले से ही संसद परिसर में धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाई गई थी। पूर्व अधिकारियों का कहना है कि ऐसे में यह कदम नियमों की स्पष्ट अवहेलना को दर्शाता है। उनके अनुसार, जब नियम पहले से निर्धारित हों, तो जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनका पालन करें और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखें। इस पूरे विवाद का सबसे चर्चित पहलू वह दृश्य रहा, जिसमें विपक्षी सांसद संसद की सीढ़ियों पर बैठकर 'चाय-बिस्किट' के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। इस पर आपत्ति जताते हुए पूर्व सैन्य अधिकारियों ने कहा कि संसद कोई सामान्य सार्वजनिक स्थल नहीं है, बल्कि यह देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है। ऐसे में वहां इस तरह का व्यवहार उसकी गरिमा के अनुरूप

नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार, यह प्रदर्शन एक गंभीर राजनीतिक मुद्दे के बजाय एक प्रतीकात्मक नाटकीयता जैसा प्रतीत हुआ, जिससे संस्था की छवि प्रभावित होती है। संयुक्त पत्र में यह भी कहा गया है कि संसद को अक्सर 'लोकतंत्र का मंदिर' कहा जाता है और इस दृष्टि से उसकी पवित्रता केवल सदन के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे परिसर में बनी रहनी चाहिए। पूर्व अधिकारियों का मानना है कि संसद की सीढ़ियां, गलियारे और अन्य स्थान भी उसी सम्मान के पात्र हैं, जैसे कि सदन के भीतर का वातावरण। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यक्तिगत या दलगत राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो एक खतरनाक प्रवृत्ति है।

इस मुद्दे को और गंभीर बनाते हुए पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया कि राहुल गांधी वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में उनके आचरण का प्रभाव केवल उनके दल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पूरे विपक्ष और व्यापक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्व अधिकारियों का कहना है कि इस पद पर रहते हुए उनका व्यवहार अनुकरणीय होना चाहिए, ताकि जनता के बीच सकारात्मक संदेश जाए।

पत्र में यह चिंता भी व्यक्त की गई है कि संसद में बार-बार होने वाले हंगामों और प्रदर्शनों के कारण जनता का समय और संसाधन दोनों प्रभावित होते हैं। संसद की कार्यवाही बाधित होने से महत्वपूर्ण विधायी कार्य रुक जाते हैं, जिससे शासन व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इसे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बताया और कहा कि राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।

अंततः, इन 204 गणमान्य व्यक्तियों ने राहुल गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की अपील की है। उनका कहना है कि यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की जिम्मेदारी है कि वे संसद की गरिमा को बनाए रखें और उसे राजनीतिक टकराव का मंच बनाने से बचें। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण पहले से ही बढ़ा हुआ है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं न केवल राजनीतिक तनाव को बढ़ाती हैं, बल्कि आम जनता के बीच भी लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर भ्रम और अविश्वास पैदा कर सकती हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राहुल गांधी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या यह विवाद किसी बड़े राजनीतिक विमर्श का रूप लेता है या समय के साथ शांत हो जाता है। फिलहाल, इतना स्पष्ट है कि संसद की गरिमा और राजनीतिक आचरण को लेकर उठे ये सवाल आने वाले समय में भी चर्चा के केंद्र में बने रहेंगे, और यह मुद्दा केवल एक दिन या एक घटना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यापक बहस का हिस्सा बन सकता है।

संपादकीय

जन्मदात्री की रक्षा

हालांकि, पंजाब में पिछले दिनों सामने आए मातृ स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े कुछ हद तक उम्मीद जरूर जगाते हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। राज्य में बच्चे को जन्म देने के दौरान मातृ मृत्यु दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। जो निश्चित रूप से गर्भावस्था और प्रसव के दौरान माताओं की सेहत की सुरक्षा करने में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की क्षमता में क्रमबद्ध सुधार का ही संकेत देती है। लेकिन, इस मामूली गिरावट के बावजूद एक गंभीर चिंता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि प्रगति अभी भी धीमी व असमान गति वाली है। दरअसल, मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों के रूप में मापी जाती है। जिसे व्यापक अर्थों में किसी भी समाज की स्वास्थ्य सेवा की क्षमता तथा समाज में लैंगिक समानता का एक महत्वपूर्ण सूचक भी माना जाता है। इस तरह मातृ मृत्यु दर में आई मामूली गिरावट भी प्रसव पूर्व गर्भवती स्त्री की देखभाल, संस्थागत स्तर पर प्रसव कराने और आपातकालीन प्रसूति सेवाओं की स्थिति में सुधार को ही दर्शाती है। इसके बावजूद अभी पंजाब में मातृ स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार की काफी गुंजाइश है। विशेष रूप से तब जब कि कई जिलों में मातृ मृत्यु दर अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। यहां जरूरी हो जाता है कि पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा में मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाए। हालांकि, पहले इस दिशा में आशातीत प्रगति दर्ज की गई थी। लेकिन अब हरियाणा की मातृ मृत्यु दर यानी एमएमआर के नवीनतम मूल्यांकन चक्र में स्थिति लगभग अपरिवर्तित ही नजर आती है। निश्चित तौर पर आंकड़ों में देखी जा रही यह स्थिरता सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में एक आम चुनौती को ही उजागर करती है। निर्विवाद रूप से प्रारंभिक स्तर पर किए गए सुधार अक्सर त्वरित लाभ देते हैं, लेकिन जरूरी है कि इस दिशा में प्रगति को अनवरत बनाया रखा जाए। निस्संदेह, इस प्रगति के लिये निरंतर गहन संरचनात्मक परिवर्तनों की जरूरत होती है।

वास्तव में मातृ स्वास्थ्य रक्षा के लिये कई मोर्चों पर एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में केवल अस्पतालों और योजनाओं में निवेश करना ही पर्याप्त नहीं होता है। बल्कि गर्भावस्था के दौरान गुणवत्तापूर्ण देखभाल, समय रहते रेफरल और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की निरंतर निगरानी करना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल, पंजाब में स्वास्थ्य संबंधी ऑडिट से पहले ही प्रणालीगत खामियों की ओर संकेत मिला है। जैसा कि निदान में देरी, प्रसवोत्तर रक्तस्राव जैसी जटिलताओं का खराब प्रबंधन तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच कमजोर समन्वय का होना भी है। निस्संदेह, इन कमियों को दूर करने के लिये जिला अस्पतालों को सुविधा संपन्न करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी जरूरत है। साथ ही ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों से रेफरल नेटवर्क में यथाशीघ्र सुधार करना भी बेहद आवश्यक हो जाता है। भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के क्रम में मातृ मृत्यु दर को प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करने का संकल्प लिया है। यदि पंजाब और हरियाणा को इस लक्ष्य को हासिल करना है तो उन्हें अपने प्रयासों में योजनाबद्ध ढंग से तेजी लानी होगी। इसमें दो राय नहीं कि मातृ मृत्यु दर महज चिकित्सा आंकड़े नहीं है। ये वो रोकी जा सकने वाली त्रासदी है, जो कई परिवारों और समुदायों को अपूरणीय क्षति पहुंचाती है। निर्विवाद रूप से इस दिशा में जहां शासन की ओर से सजगता व सतर्कता की आवश्यकता होती है, वहीं चिकित्सा तंत्र से इस दिशा में गहरी संवेदनशीलता की जरूरत होती है। निश्चित रूप से हमारे समाज में आमतौर पर श्रमिक व वंचित तबका ही सरकारी अस्पतालों का रुख करता है, जो महंगे अस्पतालों में अपनों का इलाज कराने में सक्षम नहीं होता है। वे वंश वृद्धि और मातृ रक्षा की आस में सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। निस्संदेह, पर्याप्त सुविधा का अभाव व समय पर उपचार न मिलने से होने वाली हानि व्यवस्था पर भरोसे को कम ही करती है।

राजनीतिक जंग के आगाज में लोकतांत्रिक मूल्य फिर दांव पर

> “ इन चुनावों का महत्व केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य की भी परीक्षा है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में लंबे समय से राजनीतिक संघर्ष और टकराव की स्थिति देखने को मिलती रही है। वहां सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच तीखी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है।

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि वे लोकतंत्र की परिपक्वता, जनविश्वास और राजनीतिक संस्कृति की परीक्षा भी होते हैं। जब किसी राज्य या क्षेत्र में चुनाव की घोषणा होती है तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं, आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता है और दल अपने-अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं। किंतु इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में एक संस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है-भारत का चुनाव आयोग। यही संस्था सुनिश्चित करती है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसा-मुक्त वातावरण में संपन्न हों। इस बार असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे चार बड़े राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही देश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इन पांचों स्थानों की कुल 824 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और देश के 17.4 करोड मतदाताओं के मन एवं मानसिकता की जानकारी भी मिलेगी। पिछली बार की तुलना में इस बार मतदान कम चरणों में संपन्न कराया जा रहा है, जो प्रशासनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा सकता है। असम, केरल और पुडुचेरी में जहां 9 अप्रैल को मतदान प्रस्तावित है, वहीं तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं-पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होगा। इन चुनावों की ओर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि इनके परिणाम केवल इन राज्यों की राजनीति ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य को भी प्रभावित कर सकते हैं।

इन चुनावों का महत्व केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य की भी परीक्षा है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में लंबे समय से राजनीतिक संघर्ष और टकराव की स्थिति देखने को मिलती रही है। वहां सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच तीखी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। इस प्रतिस्पर्धा के कारण कई बार चुनावी हिंसा और राजनीतिक तनाव की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। इसलिए यह चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि यह भी एक कसौटी है कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया हिंसा और भय से मुक्त रहकर संपन्न हो सकती है। लोकतंत्र का मूल आधार यह है कि प्रत्येक मतदाता बिना किसी दबाव, भय या प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में इस आदर्श को बनाए रखना आसान नहीं है। चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। इसके लिए आयोग को सुरक्षा बलों की तैनाती, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की सुरक्षा और मतदाता सूची की शुद्धता जैसे अनेक पहलुओं पर लगातार निगरानी रखनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं के आचरण पर भी नजर रखना जरूरी होता है ताकि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो।

इन चुनावों के संदर्भ में पश्चिम बंगाल विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। लंबे समय से वहां राजनीतिक हिंसा और टकराव की घटनाएं सामने आती रही हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि इस बार वहां सत्ता परिवर्तन की संभावना के कारण राजनीतिक संघर्ष और तीखा हो सकता है। सत्तारूढ़ नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली ममता बनर्जी की सरकार के सामने सत्ता बनाए रखने की चुनौती है, वहीं विपक्ष अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस परिस्थिति में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखे। दूसरी ओर केरल और तमिलनाडु की राजनीति भी अपने विशिष्ट स्वरूप के कारण चर्चा में रहती है। केरल में आमतौर पर सत्ता दो प्रमुख राजनीतिक मोर्चों के बीच बदलती रही है, जबकि तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रीय दलों के प्रभाव के लिए जानी जाती है। इन राज्यों में चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र होती है, किंतु अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान की परंपरा भी देखने को मिलती है। असम की स्थिति भी अलग है, जहां पूर्वोत्तर भारत की राजनीति के संदर्भ में चुनाव के परिणाम महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यदि वहां सत्तारूढ़ दल फिर से सत्ता में लौटता है तो यह क्षेत्रीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाएगा। ।लांकि इन सभी चुनावों के संदर्भ में एक प्रश्न लगातार उठता है कि क्या राजनीतिक दल लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करने के लिए पर्याप्त गंभीर हैं। चुनावी राजनीति में प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, किंतु जब यह प्रतिस्पर्धा हिंसा, घृणा और असहिष्णुता में बदल जाती है तो लोकतंत्र की मूल भावना को चोट पहुंचती है। दुर्भाग्य से कई बार राजनीतिक दल चुनाव जीतने की होड़ में लोकतांत्रिक शालीनता को नजरअंदाज कर देते हैं। आरोप-प्रत्यारोप, व्यक्तिगत हमले और हिंसक घटनाएं इस प्रवृत्ति के उदाहरण हैं। इस स्थिति में यह केवल चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं रह जाती कि वह चुनाव को निष्पक्ष बनाए। राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वे लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखें। यदि दल स्वयं ही आचार संहिता का सम्मान करें और अपने कार्यकर्ताओं को संयमित आचरण के लिए प्रेरित करें तो चुनावी प्रक्रिया कहीं अधिक स्वस्थ और सकारात्मक बन सकती है। लोकतंत्र की सफलता केवल संस्थाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक चेतना पर भी निर्भर करती है। इसके साथ ही मतदाताओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है। यदि मतदाता जागरूक और सजग हों तो वे ऐसे नेताओं और दलों को प्रोत्साहित करेंगे जो लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। मतदाताओं को यह समझना होगा कि उनका वोट केवल एक राजनीतिक विकल्प नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की दिशा तय करने वाला निर्णय भी है। इन पांच क्षेत्रों में होने वाले चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे यह संदेश देंगे कि भारत का लोकतंत्र किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि ये चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न होते हैं तो यह न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण होगा। भारत को अक्सर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है, इसलिए यहां होने वाली चुनावी प्रक्रिया पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नजर रहती है।

निश्चित तसौर पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं हैं, बल्कि वे लोकतंत्र के मूल्यों की परीक्षा भी हैं। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में होने वाले चुनाव इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि इन चुनावों में राजनीतिक दल संयम और जिम्मेदारी का परिचय दें, चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता और दृढ़ता बनाए रखे तथा मतदाता जागरूकता के साथ मतदान करें, तो यह लोकतंत्र की शक्ति को और अधिक सुदृढ़ करेगा। प्रश्न यह है कि क्या हम इन चुनावों के माध्यम से एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर पाएंगे, जिसमें लोकतंत्र केवल मतपेटियों तक सीमित न रहकर शालीनता, सहिष्णुता और जनविश्वास की भावना को भी मजबूत करे। यही वह कसौटी है जिस पर इन चुनावों की सफलता या असफलता का वास्तविक मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रेरणा

जब माया ने ऋषि को गृहस्थ बना दिया: चेतना के भ्रम की अनोखी लीला

एक बार देवर्षि नारद अपने स्वभाव के अनुसार लोक-लोकांतर में भ्रमण करते हुए विचारों में डूबे हुए थे। वे सदैव भगवान के नाम का गुणगान करते रहते थे और स्वयं को संसार के मोह से परे मानते थे। उन्हें लगता था कि माया केवल साधारण मनुष्यों को ही भ्रमित करती है, एक सच्चा भक्त उसके प्रभाव से दूर रहता है। इसी आत्मविश्वास के साथ वे भगवान विष्णु के धाम पहुंचे और विनम्रता से बोले कि वे उनकी माया का अनुभव करना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया कि माया को जानना आसान नहीं, परंतु नारद के आग्रह को देखते हुए उन्होंने एक लीला रचने का निश्चय किया।

भगवान ने नारद को एक विशाल वन के मध्य स्थित एक शांत झील के पास ले जाकर कहा कि वे थोड़ी देर विश्राम करें और जल लेकर आएं। नारद जल लेने के लिए झील की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने जल को स्पर्श किया, उनके भीतर कुछ विचित्र घटित होने लगा। अगले ही क्षण वे सब कुछ भूल गए—अपना नाम, अपनी पहचान, यहां तक कि भगवान से हुई बातचीत भी। वे एक युवक बन चुके थे, जिनका नाम माधव था, और जो उसी वन के समीप रहने वाले एक साधारण परिवार का हिस्सा था।

माधव के रूप में उनका जीवन बिल्कुल अलग था। वहां न तो कोई दिव्य स्मृति थी और न ही भक्ति का वैसा अनुभव। वे एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जीने लगे। धीरे-धीरे वे गांव के कार्यों में लग गए, खेती करने लगे और अपने माता-पिता की सेवा में लग गए। समय के साथ उनके जीवन में एक युवती आई, जिससे उनका विवाह हुआ। वह जीवन, जो कभी एक तपस्वी का था, अब एक गृहस्थ का बन चुका था।

वर्षों बीतते गए। माधव के बच्चे हुए, परिवार बढ़ा और जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गईं। उन्होंने अपने खेतों को संवारने में, अपने परिवार को सुरक्षित रखने में और समाज में प्रतिष्ठा पाने में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। कभी-कभी जब वे अकेले होते, तो उनके भीतर एक अजीब सी खालीपन की अनुभूति होती, जैसे कुछ छूट गया हो, लेकिन वे उसे समझ नहीं पाते। यह माया का सूक्ष्म प्रभाव था, जो उन्हें सत्य से दूर रखे हुए था।

एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। भयंकर सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हो गईं और भोजन का संकट उत्पन्न हो गया। लोग एक-दूसरे से लड़ने लगे, आपसी संबंध टूटने लगे और जीवन संघर्ष में बदल गया। माधव ने अपने परिवार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर थीं। धीरे-धीरे उनके प्रियजन उनसे दूर होते गए—कोई बीमारी से चला गया, कोई भूख से, और कोई परिस्थितियों के कारण बिछड़ गया।

माधव का हृदय टूट चुका था। वे अकेले रह गए थे, अपने जीवन की असफलताओं और पीड़ा के साथ। वे उस झील के किनारे बैठे, जहां कभी उन्होंने जल को छुआ था। उनके मन में प्रश्न उठने लगे—क्या यही जीवन है? क्या यही सत्य है? उन्होंने आकाश की ओर देखा और पहली बार उनके भीतर एक पुकार उठी, जो किसी अज्ञात शक्ति की ओर थी।

उसी क्षण एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए। उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने माधव से पूछा कि वे इतने व्यथित क्यों हैं। माधव ने अपने जीवन की पूरी कथा उन्हें सुनाई और कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। साधु मुस्कुराए और बोले कि यह सब एक स्वप्न की तरह है, जो बीत जाएगा। उन्होंने माधव से कहा कि वे उस झील में पुनः स्नान करें और अपने मन को शांत करें।

माधव ने साधु की बात मानी और जल में डुबकी लगाई। जैसे ही वे बाहर आए, सब कुछ बदल चुका था। वे फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में थे—देवर्षि नारद। उनके सामने वही वन था, वही झील थी, और भगवान विष्णु खड़े मुस्कुरा रहे थे। नारद कुछ क्षणों तक कुछ बोल ही नहीं पाए। उनके मन में जो अनुभव था, वह शब्दों से परे था।

भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि यही उनकी माया है। यह इतनी शक्तिशाली है कि वह एक ज्ञानी को भी अपने में बांध सकती है, उसे उसकी वास्तविकता से दूर कर सकती है। नारद ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि उन्होंने माया की शक्ति को कम आंका था। उन्होंने अनुभव किया कि माया केवल बाहरी वस्तुओं का आकर्षण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जाल है जो मन, बुद्धि और आत्मा को भी भ्रमित कर देता है। नारद ने यह भी समझा कि जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक वह इस माया में उलझा रहता है। चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, यदि उसके भीतर अहंकार है, तो माया उसे अपने प्रभाव में ले लेती है। यही कारण है कि भगवान ने हमेशा अपने भक्तों को विनम्रता और समर्पण का मार्ग दिखाया है।

इस अनुभव के बाद नारद का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। वे पहले की तरह केवल ज्ञान का प्रचार नहीं करते थे, बल्कि अब वे अपने अनुभव के आधार पर लोगों को समझाते थे कि जीवन में जो कुछ भी दिखाई देता है, वह अंतिम सत्य नहीं है। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि वास्तविक शांति केवल भगवान में लीन होने से ही मिलती है।

इस कथा का संदेश अत्यंत गहरा है। हम सभी अपने-अपने जीवन में माधव की तरह ही जी रहे हैं, अपने परिवार, अपने कार्य और अपनी इच्छाओं में उलझे हुए। हमें लगता है कि यही हमारा सब कुछ है, लेकिन यह सब अस्थायी है। जब तक हम इस सत्य को नहीं समझते, तब तक हम माया के जाल में फंसे रहते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है और यह समझने का प्रयास करता है कि वह वास्तव में कौन है, तब माया का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगता है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। और जब यह ज्ञान पूर्ण हो जाता है, तब मनुष्य इस संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता।

इस प्रकार यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक दर्पण है, जिसमें हम अपने जीवन को देख सकते हैं। यह हमें यह याद दिलाती है कि जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, वह एक यात्रा का हिस्सा है, न कि अंतिम गंतव्य। और जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब जीवन का हर अनुभव हमें एक नई दिशा देने लगता है।

टूट रहा है दुबई में बसने का सुनहरा सपना

बीते कुछ सालों में भारत के कई बड़े उद्योगपति, निवेशक और उच्च आय वर्ग के लोग तेजी से दुबई और खाड़ी देशों की ओर रुख करते दिखाई दिए। कम टैक्स, वैश्विक जीवनशैली और आसान बिजनेस माहौल ने उन्हें आकर्षित किया। लेकिन, हाल के भू-राजनीतिक तनावों और क्षेत्रीय अस्थिरता ने इस प्रवृत्ति पर नए सवाल खड़े कर दिए। क्या वास्तव में दुबई जैसे देशों में बसना उतना सुरक्षित और स्थायी विकल्प है जितना माना जाता है, या फिर यह केवल टैक्स बचाने और विलासितापूर्ण जीवन की चाह का परिणाम है! यह सवाल अब गंभीर बहस का विषय बन चुका है।

एक दशक में दुबई भारतीयों के लिए सबसे पसंदीदा विदेशी ठिकानों में से एक बनकर उभरा है। खासकर अमीर भारतीयों और उद्योगपतियों के बीच वहां बसने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में भारतीय निवेशकों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती गई और कई बड़े कारोबारी परिवारों ने वहां महंगी प्रॉपर्टी खरीदकर स्थायी निवास बना लिया।

इस आकर्षण के पीछे सबसे बड़ा कारण दुबई का टैक्स ढांचा है। दुबई में व्यक्तिगत आयकर नहीं है, जबकि भारत में उच्च आय वर्ग को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ता है। यही कारण है कि कई लोग अपनी आय और संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए खाड़ी देशों में बसने का फैसला करते हैं। इसके अलावा दुबई का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में पहचान और अपेक्षाकृत आसान कारोबारी नियम भी लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। हालांकि, दुबई जाने का कारण केवल टैक्स बचाना ही नहीं है। कई उद्योगपति और कारोबारी दुबई को वैश्विक व्यापार का प्रवेश द्वार मानते हैं। मध्य पूर्व, यूरोप और अफ्रीका के बीच स्थित होने के कारण दुबई व्यापार और लॉजिस्टिक्स के लिए एक रणनीतिक केंद्र बन चुका है। इसके अलावा दुबई में लग्जरी जीवनशैली, आधुनिक शहर, बेहतर परिवहन व्यवस्था और अपेक्षाकृत तेज प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी आकर्षण का कारण हैं। कई भारतीय पेशेवर और उद्यमी मानते हैं कि दुबई में कारोबार शुरू करना और विस्तार करना भारत की तुलना में आसान और तेज है। लेकिन, हाल के समय में पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों ने इस आकर्षण पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्षेत्रीय संघर्षों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने यह याद दिलाया है कि खाड़ी क्षेत्र पूरी तरह स्थिर नहीं है। जब भी पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है, तो वहां रहने वाले विदेशी नागरिकों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ जाती है। ऐसे समय में कई लोग यह महसूस करने लगते हैं कि आर्थिक लाभ के बावजूद किसी दूसरे देश में स्थायी रूप से बसना हमेशा सुरक्षित विकल्प नहीं होता। इसके विपरीत भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक और अपेक्षाकृत स्थिर देश है। यहां मजबूत संस्थाएं, स्वतंत्र न्यायपालिका और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो नागरिकों को दीर्घकालिक सुरक्षा और अधिकार प्रदान करती है। भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है और निवेश तथा उद्यमिता के नए अवसर लगातार सामने आ रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास ने देश को वैश्विक निवेश के लिए आकर्षक बना दिया है। ऐसे में कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिए विदेश बसना हमेशा दीर्घकालिक रूप से सही फैसला नहीं होता।

एक और महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का है। भारत छोड़कर विदेश में बसने वाले कई लोगों को समय के साथ यह महसूस होता है कि अपने समाज, संस्कृति और परिवार से दूर रहना आसान नहीं होता। दुबई जैसे देशों में भले ही भारतीय समुदाय बड़ा हो, लेकिन वहां की नागरिकता व्यवस्था और सामाजिक ढांचा अलग है। अधिकांश विदेशी नागरिकों को वहां स्थायी नागरिकता नहीं मिलती, जिससे उनका भविष्य हमेशा अनिश्चित बना रहता है। हाल के वर्षों में यह भी देखने को मिला है कि कुछ लोग विदेश में रहने के बाद वापस भारत लौटने का निर्णय ले रहे हैं। भारत की बढ़ती आर्थिक संभावनाएं, तकनीकी विकास और बेहतर जीवन के अवसर इस बदलाव के पीछे प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा किए गए कई आर्थिक सुधारों और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने की कोशिशों ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है।

दरअसल, विदेश में बसना या निवेश करना कोई गलत निर्णय नहीं है। लेकिन केवल टैक्स बचाने या अल्पकालिक लाभ के लिए स्थायी रूप से देश छोड़ देना एक बड़ा फैसला होता है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जरूरी यह है कि लोग आर्थिक लाभ के साथ-साथ सुरक्षा, स्थिरता, सामाजिक जुड़ाव और भविष्य की संभावनाओं जैसे पहलुओं पर भी गंभीरता से विचार करें।

दुबई और खाड़ी देशों का आकर्षण अपनी जगह है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने यह सवाल जरूर खड़ा किया है कि क्या केवल आर्थिक कारणों से विदेश बसना सही फैसला है। भारत आज तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और यहां अवसरों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में शायद यह समय है जब लोग केवल टैक्स के नजरिए से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने फैसलों पर पुनर्विचार करें।

अभियान

अनंत समय का मोड़: कृष्ण के प्रस्थान से कलियुग की कथा और मानव चेतना की नई शुरुआत

जब श्रीकृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला को समेटने का निर्णय लिया, तब वह क्षण केवल एक अवतार का अंत नहीं था, बल्कि समय की धारा में एक ऐसा मोड़ था, जहां से संपूर्ण सृष्टि का प्रवाह नई दिशा में मुड़ने लगा। द्वापर युग की अंतिम सांझ थी, जब आकाश में सूर्य अस्त होने को था और धरती पर एक अद्भुत शांति के साथ एक अनजाना कंपन भी महसूस हो रहा था। यह वही क्षण था जब ब्रह्मांड के अदृश्य नियम एक नए युग के आगमन की तैयारी कर रहे थे।

द्वारका, जो समुद्र के किनारे बसी एक अद्वितीय नगरी थी, उस समय भी अपनी भव्यता और सौंदर्य में अनुपम थी। लेकिन प्रकृति के संकेत बदलने लगे थे। समुद्र की लहरें पहले से अधिक उग्र हो उठीं, जैसे वे किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर छिपाए हुए हों। नगर के लोग इन परिवर्तनों को सामान्य मानकर अपने जीवन में व्यस्त थे, परंतु समय के गर्भ में एक ऐसा परिवर्तन पनप रहा था, जो सब कुछ बदल देने वाला था।

इसी समय यादव वंश, जो श्रीकृष्ण के संरक्षण में पला-बढ़ा था, अपने ही अहंकार और मतभेदों के कारण पतन की ओर बढ़ चुका था। एक समय जो वंश पराक्रम और एकता का प्रतीक था, वही अब अपने ही हाथों अपने अस्तित्व को समाप्त कर रहा था। यह केवल एक वंश की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस युग की नियति थी, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच का संतुलन टूटने लगा था।

बलराम, जो सदैव स्थिरता और शक्ति के प्रतीक रहे, इस सब से विरक्त होकर वन में चले गए। उन्होंने संसार के बंधनों को त्यागकर योग की परम अवस्था में अपने प्राणों का विसर्जन किया। उनके प्रस्थान के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि अब श्रीकृष्ण के पृथ्वी पर रहने का समय भी समाप्ति की ओर है।

श्रीकृष्ण ने जब अपने वंश के अंत को देखा, तो उनके मन में कोई शोक नहीं था। वे जानते थे कि यह सब समय का खेल है, और हर घटना एक निश्चित योजना के अंतर्गत घटित होती है। वे वन में गए, जहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया। उनका शरीर स्थिर था, परंतु उनकी चेतना ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो चुकी थी।

उसी समय एक शिकारी, जरा, वहां आया। उसने दूर से श्रीकृष्ण के चरण को किसी पशु का अंग समझ लिया और बाण चला दिया। वह बाण आकर उनके चरण में लगा। जैसे ही यह हुआ, श्रीकृष्ण ने अपनी आंखें खोलीं और उस शिकारी को देखा, जो भय और पश्चाताप से कांप रहा था। श्रीकृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा कि यह सब पूर्व निर्धारित था। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और अपने प्राणों को समेटकर ब्रह्म में विलीन हो गए।

जैसे ही श्रीकृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया, उसी क्षण द्वापर युग का अंत हो गया और कलियुग का प्रारंभ हुआ। यह परिवर्तन केवल समय का नहीं था, बल्कि यह मानव चेतना के स्तर में भी एक बड़ा परिवर्तन था। कलियुग में मनुष्य का मन अधिक चंचल, अधिक भौतिक और अधिक स्वार्थी हो जाता है। लेकिन इसी युग में भक्ति का मार्ग भी सबसे सरल हो जाता है।

श्रीकृष्ण के प्रस्थान के तुरंत बाद द्वारका में भीषण परिवर्तन शुरू हो गए। समुद्र की लहरें इतनी तीव्र हो गईं कि उन्होंने पूरे नगर को अपने भीतर समेट लिया। वह नगरी, जो कभी समृद्धि और धर्म का प्रतीक थी, अब केवल इतिहास की एक कथा बनकर रह गई। यह दृश्य यह दर्शाता है कि संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, चाहे वह कितनी ही महान क्यों न हो।

इसी समय एक और कथा जन्म लेती है, जो इस युग परिवर्तन की गहराई को और भी स्पष्ट करती है। एक साधारण चरवाहा, जो द्वारका के पास के एक गांव में रहता था, इन घटनाओं का साक्षी बना। उसने देखा कि कैसे एक समृद्ध नगर कुछ ही समय में समुद्र में समा गया। यह दृश्य उसके मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न कर गया। वह चरवाहा अपने गांव लौट आया, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी। उसने अपने जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश शुरू की। वह एक ऋषि के पास गया और उनसे पूछा कि यह सब क्यों हुआ। ऋषि ने उसे बताया कि यह सब समय का चक्र है, जिसमें हर चीज का एक निश्चित स्थान और समय होता है। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य अपने अहंकार में डूब जाता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है।

चरवाहे ने यह बात अपने हृदय में धारण कर ली। उसने अपने जीवन को सरल और संतुलित बनाने का प्रयास किया। उसने समझ लिया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। यह परिवर्तन केवल उसके जीवन में नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों के जीवन में भी दिखने लगा। समय के साथ यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता गया। ऋषियों ने इसे शास्त्रों में संजोया और समाज को यह सिखाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति करना है। इसी कालखंड में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष के रूप में मानने की परंपरा स्थापित हुई। यह वह दिन था जब एक नया युग शुरू हुआ था, और इसी कारण इसे एक नई शुरुआत का प्रतीक माना गया। इस दिन को विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे उगादी, गुड़ी पड़वा आदि।

बाद में सम्राट विक्रमादित्य ने इस परंपरा को और सुदृढ़ किया। उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त कर विक्रमी संवत की स्थापना की, जो आज भी भारतीय कालगणना का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि यह उस सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, जो समय के साथ भी जीवित रहती है।

इसी प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था, जो धर्म और न्याय के आदर्शों का प्रतीक था। और बाद में महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भी इसी दिन आर्य समाज की स्थापना कर समाज में वैदिक ज्ञान को पुनर्जीवित किया।

समय का यह चक्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। हर युग का अपना महत्व है और हर युग हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कलियुग भले ही चुनौतियों से भरा हो, लेकिन यह आत्मचिंतन और आत्मज्ञान का भी एक अवसर है।

श्रीकृष्ण का प्रस्थान हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम जीवन के हर उतार-चढ़ाव को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं।

अंततः यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि हम केवल समय के प्रवाह में बहने वाले जीव नहीं हैं, बल्कि हम उस चेतना का हिस्सा हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तब हम माया के बंधनों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ सकते हैं।

इस प्रकार, श्रीकृष्ण के महाप्रस्थान की यह कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है, जो हमें अपने जीवन को समझने और उसे सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का दक्षिण गुजरात के पर्यटन को सुपर बूस्ट : अब पलक झपकते ही पहुंच जाएंगे सुदूरवर्ती जंगलों में

▸▸ दक्षिण गुजरात की खूबसूरत वादियों का सफर अब और भी सुगम और सुहाना होगा

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत के पर्यटन क्षेत्र ने की शानदार प्रगति, वर्ष 2024 में विदेश से आने वाले पर्यटकों में 14.85 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में भारत के पर्यटन मानचित्र में गुजरात विशेष रूप से उभरकर सामने आया : वर्ष 2024 में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में गुजरात देश भर में तीसरे स्थान पर

▸▸ मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक अहमदाबाद-दांडी हेरिटेज रूट, पारसी टूरिज्म सर्किट, सूरत, तापी, डांग और नवसारी की इको-टूरिज्म साइट को जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा और अपग्रेड करने के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की

जीएनएस)। गांधीनगर : यदि आप अहमदाबाद, वडोदरा या सूरत जैसे बड़े शहरों में रहते हैं और वीकेंड पर शहर के कोलाहल से दूर दक्षिण गुजरात में प्रकृति की गोद में तरोताजा होने के लिए प्राकृतिक जंगलों एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर घूमना चाहते हैं, तो अब आपको कोई बड़ा प्लान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पलक झपकते ही वहां पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने दक्षिण गुजरात में स्थित पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा और अपग्रेड करने के लिए सुपर बूस्ट दिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने सूरत इकोनॉमिक रीजन (एसईआर) योजना (फेज-1) के अंतर्गत सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड और डांग जैसे जिलों में अलग-अलग सड़कें बनाने और अपग्रेड करने के लिए 1185 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि आवंटित की है। इस योजना में पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के लिए भी बड़ी राशि आवंटित की गई है। इस योजना के तहत जिलों में सड़कों को चौड़ा तथा मजबूत किया जाएगा, आवश्यक जगहों पर फोर और सिक्स लेन सड़कें बनाई जाएंगी तथा कुछ शहरों में बाईपास सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा। इससे दक्षिण गुजरात के पर्यटन स्थलों का सफर और भी सुगम एवं सुहाना हो जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत के पर्यटन क्षेत्र ने शानदार प्रगति की है। वर्ष 2024 में विदेश से आने वाले सैलानियों में 14.85 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में भारत के पर्यटन मानचित्र में गुजरात विशेष रूप से उभरकर सामने आया है। वर्ष 2024 में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में गुजरात देश भर में तीसरे स्थान पर रहा है।

अब सुरत के सुवाली बीच का सफर होगा और भी आसान

सूरत के शांत और सुरम्य समुद्र तट यानी सुवाली बीच तक जाने वाले मोरा-सुवाली बीच रोड के विकास से सुवाली बीच तक जाना अब और भी आसान हो जाएगा। सुवाली बीच सूरत जिले के एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। यहां आयोजित होने वाला 'सुवाली बीच फेस्टिवल' अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। सड़क के विकास से पर्यटन गतिविधियों को अधिक बढ़ावा मिलने के साथ-साथ क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी एक नई गति मिलेगी।

कोस्टल हाईवे फेज-1 के तहत सुवाली बीच रोड को 10.00 मीटर चौड़ा किया गया था। इसके बाद सुवाली बीच को सूरत जिले के पर्यटन मानचित्र में शामिल किया गया। अब इस बीच के नजारों को देखने के लिए हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं। इसलिए, मोरा से सुवाली बीच रोड को फोरलेन किया जाएगा।

आसान होगा रजवाड़ी नगर धरमपुर का सफर

चिखली से खेरगाम होते हुए धरमपुर जाने वाली सड़क को फोरलेन बनाया जाएगा, इससे धरमपुर जाना और भी आसान हो जाएगा। इस सड़क के चौड़ा होने से मानसून में प्रकृति की गोद में बसे धरमपुर और विल्सन हिल जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी।

दक्षिण गुजरात प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली से समृद्ध क्षेत्र है। यहां अनेक पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थान हैं, जो सुकून और शांति की अनुभूति कराते हैं। इनमें केवड़ी इको-टूरिज्म साइट (मांडवी), पदमडुंगरी इको-टूरिज्म साइट (डोलवण), उनाई मंदिर (वांसदा), वघई बॉटनिकल गार्डन, वांसदा नेशनल पार्क (वांसदा), पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य और गिरा जलप्रपात जैसे अनेक स्थानों पर प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को निहारने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। इसलिए, इन पर्यटन स्थलों पर आने वाले सैलानियों को एक सुखद अनुभव देने और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी से पर्यटन विकास को एक नई ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री ने दक्षिण गुजरात में पर्यटन स्थलों के अवसंरचना विकास के लिए यह बड़ी धनराशि आवंटित की है। सरकार के इन प्रयासों से पर्यटन स्थलों के विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र भी साकार होगा।

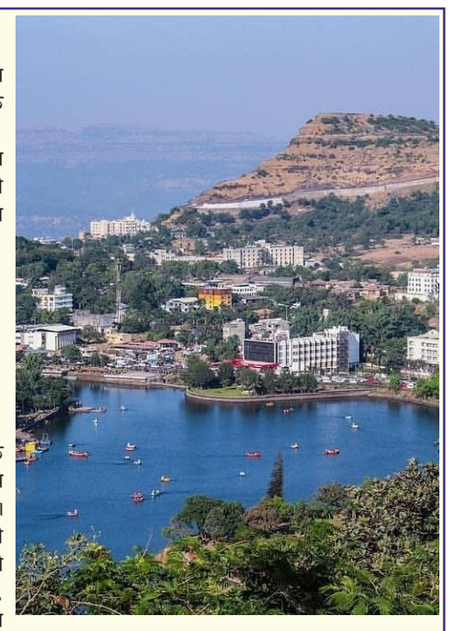

ऐतिहासिक अहमदाबाद-दांडी हेरिटेज रूट बनेगा नयनरम्य

महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा के रूट पर अब आसानी से यात्रा की जा सकेगी। यह सड़क अहमदाबाद-दांडी हेरिटेज रूट पर आने वाले कदरामा, एरथाण, टकरामा, भटगाम, मोहंमदपुरा, गोला और सांधियेर गांवों को जोड़ती है। इस सड़क को तीन मीटर से सात मीटर चौड़ा किया जाएगा, जिससे यातायात का बोझ कम होने से इस ऐतिहासिक मार्ग का दौरा करना सुगम हो जाएगा।

कोस्टल हाईवे के जरिए संजाण और दमन अब और करीब हुए

वलसाड जिले में उमरसाडी से कोलक नदी कोस्टल हाईवे पर एक कॉज-वे बनेगा। यह कोस्टल हाईवे वलसाड और दमन को जोड़ने वाली एक अहम सड़क है। प्राकृतिक नजारों से भरपूर यह नयनरम्य सड़क दमण, उदवाड़ा अगियारी, उमरसाडी वॉक-वे ब्रिज आदि पर्यटन स्थलों को जोड़ती है। मौजूदा 10 मीटर सड़क को अब चौड़ा करके फोरलेन बनाया जाएगा।

डांग का प्राकृतिक सौंदर्य अब शहरों से दूर नहीं

गुजरात का सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल डांग जिला अब दूर नहीं लगेगा। प्रकृति और संस्कृति के इस संगम स्थान की प्राकृतिक छटा को देखने के लिए कुछ ही देर में पहुंचा जा सकता है। डांग में वघई से आहवा जाने वाला राज्य राजमार्ग (स्टेट हाईवे) डांग जिले के अन्य गांवों को जिला मुख्यालय के साथ जोड़ता है। यह हाईवे पर्यटन एवं यात्राधाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सड़क शबरीधाम, पंपा सरोवर, अग्निकुंड और पांडव गुफा जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों और डॉन हिल स्टेशन, महाल कैंप साइट, देविनामाळ कैंप साइट, सापुतारा हिल स्टेशन और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे पर्यटन स्थलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह सड़क अब फोरलेन हो जाएगी, जिससे लोग सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्थलों तक जल्द पहुंच सकेंगे।

नेशनल डिफेंस कॉलेज के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से की शिष्टाचार भेंट

▸▸ 'नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक स्टडी' कार्यक्रम के तहत इकोनॉमिक सिक्योरिटी के स्टडी प्रोग्राम में 122 अधिकारी भाग ले रहे हैं

▸▸ गुजरात दौरे के दौरान 17 सदस्यीय दल ने गिफ्ट सिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इंडो-इजरायल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एग्रीकल्चर और जामनगर का दौरा किया

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात ने उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण और कृषि विकास सहित सभी क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्य को हासिल किया है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ एनडीसी के अधिकारियों ने गुजरात के समग्र आर्थिक विकास की गाथा जानने में दिखाई उत्सुकता

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से मंगलवार को गांधीनगर में नई दिल्ली स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) के स्टडी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सदस्यों के दल ने शिष्टाचार मुलाकात की। नेशनल डिफेंस कॉलेज भारतीय सशस्त्र बलों के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों, सिविल सेवा के संयुक्त सचिवों और निदेशक स्तर के अधिकारियों तथा साझेदार देशों के विदेशी सैन्य अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक अभ्यास पर पाठ्यक्रम चलाता है।

इस वर्ष इकोनॉमिक सिक्योरिटी विषय पर आधारित स्टडी कार्यक्रम की बैच में भारतीय सशस्त्र बलों को 61, सिविल सेवा के 20 और पार्टनर फॉरेन कंट्रीज के 41 सहित कुल 122 अधिकारी शामिल हैं।

इस स्टडी कार्यक्रम के दौरान देश के अलग-अलग राज्यों के अध्ययन दौरे के तहत गुजरात की यात्रा पर पहुंचे रियर एडमिरल श्री संदीप सिंह संधू के नेतृत्व में एनडीसी के 17 अधिकारियों के दल ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। इस दल में भारतीय सेना के तीनों अंगों के अलावा भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस), कम्युनिकेशन सर्विसेज तथा पार्टनर कंट्रीज के सैन्य अधिकारी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ इस मुलाकात के दौरान एनडीसी के अधिकारियों ने गुजरात के समग्र आर्थिक विकास की गाथा के बारे में जानने में उत्सुकता दिखाई। विशेषकर, महिला सशक्तिकरण, संतुलित आर्थिक विकास और तीव्र गति से हो रहे

विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ रोचक संवाद किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस संदर्भ में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात ने नीति-संचालित राज्य (पॉलिसी ड्रिवेन स्टेट) के रूप में ख्याति अर्जित की है और विकास का रोल मॉडल बना है। वाइब्रेंट समिट के जरिए गुजरात दुनिया भर के उद्योगों और निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुजरात ने औद्योगिक विकास के साथ-साथ ग्रीन ग्रोथ और संतुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया है।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को विस्तार से बताया कि सरदार साहब की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से टूरिज्म को और वोकल फॉर लोकल से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिला है। राज्य में 24 घंटे निर्बाध बिजली, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और विशाल कैनाल नेटवर्क के माध्यम से नर्मदा का पानी कच्छ तक पहुंचाने से राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकास की प्रत्येक योजना आम नागरिक को केंद्र में रखकर बनाई है। इतना ही नहीं, सैचुरेशन एप्रोच अपनाकर, जिनके लिए योजना बनी है, उन जरूरतमंद लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाकर 100 फीसदी सफलता का लक्ष्य भी उनके मार्गदर्शन में हासिल हो रहा है।

मुख्यमंत्री के साथ आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे भी मौजूद रहे।

पश्चिम रेलवे एवं एसबीआई द्वारा दिवंगत रेल कर्मचारी के परिजनों को 1 करोड़ रुपये का बीमा भुगतान सौंपा गया

जीएनएस)। कर्मचारी कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल के एक वरिष्ठ मोटरमैन, जिनका ड्यूटी के दौरान एक दुर्घटना में दुखद निधन हो गया था, उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की बीमा राशि प्रदान की गई।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह मुंबई सेंट्रल मंडल में इस प्रकार का पहला बीमा भुगतान है, जो सितंबर 2025 में भारतीय रेल और भारतीय स्टेट बैंक के बीच उन्नत रेलवे सैलरी पैकेज (RSP) योजना के अंतर्गत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत संभव हो पाया।

मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह तथा भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई मेट्रो सर्कल की मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती मंजू शर्मा ने 16 मार्च, 2026 को मुंबई सेंट्रल मंडल कार्यालय में आयोजित एक गरिमामय समारोह में दिवंगत कर्मचारी की पत्नी

को एक करोड़ रुपये का चेक सौंपा। इस अवसर पर रेलवे एवं एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुंबई सेंट्रल मंडल के कार्मिक विभाग ने सभी देयकों के समयबद्ध भुगतान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें एक्स-ग्रेशिया तथा अन्य पात्र मुआवजे शामिल हैं। यह बीमा राशि, रेलवे की नीति के अनुसार पहले से प्रदान किए गए अन्य सेटलमेंट लाभों के अतिरिक्त है।

आरएसपी योजना के अंतर्गत, एसबीआई में वेतन खाते रखने वाले रेल कर्मचारियों को व्यापक बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ बीमा सुरक्षा भी प्राप्त होती है, जिसमें बिना किसी प्रीमियम या चिकित्सीय जांच के एक करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर शामिल है। दिवंगत वरिष्ठ मोटरमैन ने इस योजना का लाभ लिया था, जिससे उनके आश्रितों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी। यह पहल भारतीय रेल द्वारा अपने कर्मचारियों के कल्याण तथा उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को राज्य में समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी गई

सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी समिति ने सूक्ष्म अध्ययन, जिलों की यात्रा तथा जनसंपर्क के बाद चर्चा-विचार के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी

जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के क्रियान्वयन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को मंगलवार को गांधीनगर में अपनी विस्तृत तथा अंतिम रिपोर्ट सौंपी।

यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी समिति ने सूक्ष्म अध्ययन कर, राज्य के जिलों की यात्रा कर, लोक अभिप्राय प्राप्त करके तथा व्यापक जनसंपर्क के बाद चर्चा-विचार के आधार पर तैयार की गई, जो राज्य सरकार को सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित इस समिति में सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस श्री सी. एल. मीणा, वरिष्ठ एडवोकेट श्री आर. सी. कोडेकर, पूर्व कुलपति डॉ. दक्षेश ठाकर तथा सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती गीता श्रॉफ शामिल हैं। मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रेजेंटेशन में बताया गया कि इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में विवाह, तलाक, विरासत में मिलने वाली संपत्ति और दत्तक जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों और समुदायों के

लिए समान कानूनी ढांचा समिति द्वारा सुझाव दिया गया है।

विशेष रूप से महिलाओं के समान अधिकारों और सुरक्षा को इस ड्राफ्ट में प्राथमिकता दी गई है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में गुजरात की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को भी ध्यान में रखा गया है।

गुजरात में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के क्रियान्वयन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने मुख्यमंत्री को इस रिपोर्ट की तीन वॉल्यूम सौंपी। इस अवसर पर समिति के सलाहकार, सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस तथा उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह, समिति के सदस्य, मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, वैधानिक मामलों के सचिव श्री के. एम. लाला, कानून सचिव श्री उपेंद्र भट्ट तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

पिंक टॉयलेट: गुजरात के शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की सुविधा और स्वच्छता के लिए गुजरात सरकार की नई पहल

▸▸ निर्मल गुजरात 2.0 के तहत राज्य के महानगर पालिका-नगर पालिका क्षेत्रों और शहरी पवित्र यात्राधाम क्षेत्रों में महिलाओं के लिए बनेंगे स्वच्छ और आधुनिक पिंक टॉयलेट

▸▸ वर्ष 2026-27 के राज्य के बजट में पिंक टॉयलेट के लिए 59.14 करोड़ का प्रावधान

▸▸ निर्मल गुजरात 2.0 पहल के तहत गुजरात को देश में स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रसर बनाने के लिए पिंक टॉयलेट के निर्माण सहित 4 नए घटकों का समावेश

जीएनएस)। गांधीनगर : वर्ष 2007 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई निर्मल गुजरात योजना का दायरा आज बड़े पैमाने पर बढ़ गया है, जो अब केवल स्वच्छता गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में निर्मल गुजरात 2.0 अभियान शुरू किया है और राज्य के शहरी इलाकों में नागरिकों के बीच स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूकता पैदा करने और गुजरात को देश में स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वच्छता से संबंधित निर्मल गुजरात 2.0 के तहत चार नए घटक शामिल किए गए हैं। इन चार घटकों में से एक है महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण। महिलाओं की सुविधा और स्वच्छता के लिए गुजरात के महानगर पालिका-नगर पालिका क्षेत्रों और शहरी पवित्र यात्राधाम क्षेत्रों तथा तीर्थस्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा।

महिलाओं के लिए सुविधाजनक पिंक टॉयलेट की विशेषताएं

गुजरात सरकार ने हमेशा महिलाओं के

लिए स्वच्छता, सुविधा और सुरक्षा पर जोर दिया है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में बनाए जाने वाले पिंक टॉयलेट में कई सुविधाएं होंगी, जैसे कि 4 नॉर्मल टॉयलेट सीट, दिव्यांग महिलाओं के लिए 1 सीट, चेंजिंग रूम, बच्चों को दूध पिलाने के लिए रूम और महिला केयरटेकर क्षेत्र जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। पिंक टॉयलेट के निर्माण के लिए वर्ष 2026-27 के राज्य सरकार के बजट में 59.14 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। हाल ही में, जब पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, तब पिंक टॉयलेट्स के निर्माण का यह निर्णय राज्य सरकार की महिलाओं के लिए स्वच्छता व सुरक्षा बनाए रखने की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।

वर्ष 2026-27 में 'निर्मल गुजरात 2.0' अंतर्गत 4 नए घटकों का समावेश

वित्तीय वर्ष 2026-27 में 'निर्मल गुजरात 2.0' के तहत कुल 4 नए घटकों को शामिल किया गया है, जिनमें 1) स्वच्छ शहर – ठोस कूड़ा संग्रहण (डोर टु डोर कलेक्शन सुदृढ़ करना), 2) महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण, 3) पब्लिक टॉयलेट्स का संचालन और रखरखाव और 4) नदियों की सफाई शामिल है। इसके लिए इस वर्ष के राज्य के बजट में कुल 329.54 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन नए घटकों के माध्यम से 100% डोर टु डोर वेस्ट कलेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा और 'स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0' के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित सभी सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव और संचालन अधिक प्रभावी ढंग से किया जाएगा।

ऊना कांड पर दशक बाद फैसला: 37 आरोपी बरी, 5 को सजा—देशव्यापी बहस फिर तेज

जीएनएस)। अहमदाबाद। लगभग एक दशक तक चले लंबे इंतजार, सैकड़ों गवाहियों और देशव्यापी बहस के बाद गुजरात के बहुचर्चित ऊना दलित हिंसा मामले में अदालत का फैसला सामने आ गया है। 2016 में घटी इस दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और अब 10 साल बाद आए इस निर्णय ने एक बार फिर उसी बहस को जीवंत कर दिया है, जो उस समय सड़कों से लेकर संसद तक गूंज रही थी। अदालत ने इस मामले में 42 आरोपियों में से 37 को बरी कर दिया है, जबकि 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। इस फैसले ने न्यायिक प्रक्रिया, जांच की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय की स्थिति को लेकर कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

यह घटना 11 जुलाई 2016 को गुजरात के मोटा समढियाला गांव में हुई थी, जहां दलित समुदाय के चार युवकों को कथित गोकशी के आरोप में भीड़ द्वारा बेरहमी से पीटा गया था। उन्हें सार्वजनिक रूप से अधनंगा कर लाठियों और बेल्टों से मारा गया, और इस अमानवीय कृत्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। यही वीडियो इस घटना को स्थानीय दायरे से निकालकर राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना गया। उस समय देशभर में व्यापक आक्रोश देखने को मिला था और दलित समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे।

पीड़ितों का कहना था कि वे कोई अवैध कार्य नहीं कर रहे थे, बल्कि मृत पशुओं की खाल उतारने का पारंपरिक काम करते थे। इसके बावजूद उन्हें निशाना बनाया गया। इस घटना ने यह सवाल उठाया कि क्या केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को इस तरह सजा दी जा सकती है, और क्या कानून का स्थान भीड़ ने ले लिया है। यह मामला भीड़ हिंसा और तथाकथित 'गौरक्षक' गतिविधियों पर भी राष्ट्रीय बहस का कारण बना।

घटना के बाद पुलिस ने कुल 42 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपियों पर हत्या के प्रयास, डकैती, अपहरण, दंगा और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई थीं। लेकिन जैसे-जैसे मामला अदालत में आगे बढ़ा, कई आरोपों

को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिल सके। करीब 10 साल तक चली इस सुनवाई में 260 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जो इस केस की जटिलता और व्यापकता को दर्शाता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हत्या के प्रयास, डकैती और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसी आधार पर 37 आरोपियों को बरी कर दिया गया। वहीं, पांच आरोपियों के खिलाफ ऐसे प्रमाण मिले, जिनके आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया और पांच साल की सजा सुनाई गई। इस फैसले में यह भी सामने आया कि कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ लगाए गए आरोप भी सिद्ध नहीं हो सके, जिसके चलते उन्हें भी राहत मिल गई। इस दौरान दो आरोपियों की मृत्यु भी हो चुकी है, जिससे मामले का स्वरूप और जटिल हो गया था। यह फैसला केवल कानूनी दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2016 में जब यह घटना हुई थी, तब इसने देश में दलितों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर एक बड़ा विमर्श खड़ा किया था। कई सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने इसे संस्थागत असमानता और कमजोर वर्गों के खिलाफ हिंसा का उदाहरण बताया था। उस समय गुजरात सहित देश के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर आंदोलन हुए थे, जिन्होंने सरकार और प्रशासन को कठघरे में खड़ा कर दिया था। अब जब अदालत का फैसला आया है, तो एक बार फिर वही सवाल सामने आ रहे हैं—क्या न्याय हुआ है, या न्यायिक प्रक्रिया में कहीं कमी रह गई? जहां एक ओर कुछ लोग इसे अदालत के तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित निष्पक्ष निर्णय मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि इतने बड़े और चर्चित मामले में अधिकांश आरोपियों का बरी होना न्याय की भावना के विपरीत है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी आपराधिक मामले में भावनाओं के बजाय ठोस साक्ष्य और कानूनी प्रक्रिया ही निर्णायक होती है। यदि जांच के दौरान पर्याप्त और मजबूत प्रमाण इकट्ठा नहीं किए जाते, तो अदालत के लिए दोष सिद्ध करना कठिन हो जाता है। इस दृष्टिकोण से यह मामला जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और उनकी क्षमता पर भी सवाल उठाता है।

इसके साथ ही यह मामला भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव की गहरी जड़ों को भी उजागर करता है। ऊना कांड ने यह दिखाया था कि सामाजिक पूर्वाग्रह किस तरह हिंसा का रूप ले सकते हैं। यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रतीक बन गई थी, जिसने समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति को उजागर किया। आज, एक दशक बाद, जब इस मामले का न्यायिक निष्कर्ष सामने आया है, तब यह जरूरी हो जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम से सीख ली जाए। कानून व्यवस्था को मजबूत करना, जांच प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना और समाज में समानता तथा न्याय की भावना को बढ़ावा देना—ये सभी ऐसे कदम हैं, जिन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

ऊना कांड का यह फैसला केवल अतीत का निष्कर्ष नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए एक चेतावनी भी है। यह हमें याद दिलाता है कि न्याय केवल अदालतों में नहीं, बल्कि समाज के हर स्तर पर सुनिश्चित होना चाहिए। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस फैसले के बाद सरकार, न्यायपालिका और समाज किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और क्या यह घटना वास्तव में एक स्थायी बदलाव का कारण बन पाती है या नहीं।

अहमदाबाद रेल मंडल में 'कवच 4.0' का तेजी से विस्तार: सुरक्षित सफर की ओर बढ़ते कदम; अहमदाबाद–पालनपुर, सामाख्याली एवं गांधीधाम रेल मार्गों पर कवच इंस्टालेशन कार्य प्रगति पर

जीएनएस)। कवच 4.0 एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली है। कवच एक उच्च प्रौद्योगिकी युक्त प्रणाली है, जिसके लिए उच्चतम क्रम (एसआइएल-4) के सुरक्षा प्रमाणन की आवश्यकता होती है। कवच लोको पायलट को निर्धारित गति सीमा के भीतर ट्रेन चलाने में सहायता करता है, लोको पायलट के ऐसा करने में विफल रहने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर और खराब मौसम के दौरान ट्रेनों को सुरक्षित रूप से चलाने में भी मदद करता है। यह भारतीय रेलवे के लिए सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कवच भारतीय रेल द्वारा विकसित एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, इसका उद्देश्य ट्रेनों की टक्कर को रोकना, सिग्नल उल्लंघन (SPAD) से बचाव करना तथा सुरक्षित और नियंत्रित संचालन सुनिश्चित करना है। इस प्रणाली में RFID (Radio Frequency Identification) तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसके तहत ट्रैक पर RFID टैग लगाए जाते हैं और लोकोमोटिव में लगे रीडर के माध्यम से ट्रेन की सटीक लोकेशन, सिग्नल की स्थिति तथा गति सीमा की जानकारी प्राप्त होती है।

अहमदाबाद मंडल में 'कवच' प्रणाली का क्रियान्वयन

भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विकसित की गई उन्नत स्वदेशी प्रणाली 'कवच' का क्रियान्वयन अहमदाबाद मंडल में भी तीव्र गति से किया जा रहा है। यह प्रणाली ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित, उत्तरदायी तथा नियंत्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

1. वटवा लोको शेड में कवच कार्य की प्रगति

वटवा लोको शेड में कुल 180 इंजनों पर 'कवच' प्रणाली स्थापित करने की योजना है। अब तक 72 इंजनों पर यह कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष इंजनों पर कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के लिए प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की एक समर्पित टीम नियुक्त की गई है, जो चरणबद्ध रूप से कवच की स्थापना का कार्य कर रही है।

2. साबरमती लोको शेड में कवच कार्य की प्रगति साबरमती लोको शेड में 34 इंजनों पर कवच स्थापित किया जाना है। इनमें से अब तक 6 इंजनों पर ट्रायल सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष इंजनों पर कार्य जारी है। इस कार्य हेतु तकनीकी कर्मचारी तैनात हैं, जो कवच की सूक्ष्म स्थापना प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं।

3. ट्रैक सेक्शनों पर कवच इंस्टालेशन की स्थिति

- अहमदाबाद–पालनपुर एवं अहमदाबाद–सामाख्याली सेक्शन (कुल 402 आरकेएम): इस रेलखंड पर 410.10 करोड़ रुपये की लागत से कवच इंस्टॉलेशन का कार्य प्रगति पर है।
- पालनपुर–सामाख्याली–गांधीधाम सेक्शन (300 आरकेएम): इस खंड पर 182.81 करोड़ रुपये की लागत से कवच इंस्टॉलेशन का कार्य प्रगति पर है।
- अहमदाबाद–गेरतपुर सेक्शन (13.42 किमी): इस सेक्शन पर कवच प्रणाली की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है और यह खंड अब कवच से सुसज्जित हो गया है।
- अहमदाबाद डिविजन के सभी सेक्शनों में RFID टैग सफलतापूर्वक लगाए जा चुके हैं तथा कवच-फिटेड लोको का ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है।
- हाल ही में गांधीनगर कैपिटल और कलोल के बीच लगभग 20 किमी सेक्शन में सफल ट्रायल किया गया।
- ट्रायल के दौरान दो ट्रेनों को एक ही ट्रैक के एक ही ब्लॉक सेक्शन में चलाया गया। जैसे ही दोनों लोको लगभग 10 किमी की दूरी के भीतर आए, पीछे चल रहे लोको में स्वतः ब्रेक लग गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि एक ही ब्लॉक सेक्शन में दो ट्रेनों को आगे-पीछे नहीं चलाया जा सकता।
- किसी भी ट्रेन के एक ही ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करते ही स्वतः ब्रेक लग जाता है तथा चेतावनी स्वरूप हॉर्न भी बजने लगता है।
- जब दोनों लोको को आमने-सामने लाने का प्रयास किया गया, तब भी दोनों लोको में स्वतः ब्रेक लग गया, जिससे संभावित टक्कर टल गई।
- दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा के घनी आबादी वाले मार्गों पर 1,452 रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 का सफल संचालन शुरू हुआ।
- रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए 8,570 किमी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई, 1,100 टावर और 6,776 रूट किमी ट्रैकसाइड उपकरण स्थापित किए गए, तथा 767 स्टेशन डेटा सेंटर स्थापित किए गए.
- भारतीय रेलवे के सभी गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, गोल्डन डायगोनल, हाई डेंसिटी नेटवर्क और चिन्हित खंडों को कवर करते हुए 24,427 रूट किमी ट्रैकसाइड कवच कार्यान्वयन कार्य शुरू किया गया है।
- भारतीय रेलवे की यह पहल न केवल सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, बल्कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से ट्रेन संचालन को अधिक उत्तरदायी और नियंत्रित बनाती है। अहमदाबाद मंडल रेलवे सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और 'कवच' प्रणाली इसके भविष्य के लिए एक मजबूत आधारशिला सिद्ध हो रही है।

आरबीआई ने भ्रष्टाचार और नियामक उल्लंघनों के लिए सूरत के सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। आम तौर पर सहकारी बैंकों की शुरुआत सदस्यों को आसानी से वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जाती है। यही बात सार्वजनिक रूप से चर्चा में है। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। सहकारी बैंकों को सरकार और आरबीआई द्वारा निर्धारित नियमों और कानूनों का सख्ती से पालन करना होता है। लेकिन शायद ही कोई बैंक इनका पालन करता है। और सहकारी बैंकों में भी भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन व्याप्त है। आरबीआई द्वारा ऐसे बैंकों पर लगाए गए जुर्माने से पता चलता है कि जुर्माना जितना अधिक होता है, घोटाले उतने ही बड़े होते हैं। सहकारी बैंकों के प्रशासकों की प्रशासनिक विफलताओं के कारण बैंकों पर इतने भारी जुर्माने लगाए गए हैं। अधिकांश प्रशासक अपने अहंकार और शीर्ष पर पहुंचने के भ्रम में जी रहे हैं।

इसी कारण वे बैंकों को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाते हैं और बैंक की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं। आम सदस्यों को बैंक के भ्रष्ट अधिकारियों के पापों का खामियाजा भुगतना पड़ता है।

जिन बैंकों पर वित्तीय दंड लगाया गया है, उनका विवरण इस प्रकार है। हालांकि, बैंक निदेशकों, जिला रजिस्ट्रार और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं किया गया है। सूरत जिला सहकारी बैंक लिमिटेड (जनवरी 2026): पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ) दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने और ऋण/अग्रिम प्रबंधन नियमों का अनुपालन न करने के लिए 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। मांडवी नागरिक सहकारी बैंक, सूरत (जुलाई 2025): स्वीकृत ऋणों के संबंध में निधियों के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने में चूक, विशेष रूप से ऋणों के प्रबंधन के संबंध में, के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। पंचशील मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (सितंबर 2025): इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन से संबंधित ग्राहक सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। सूरत नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक (सितंबर 2023): परिपक्व जमाओं पर ब्याज का भुगतान न करने और ग्राहकों को धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की तत्काल रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने में विफल रहने के लिए जुर्माना लगाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में गुजरात के सूरत में स्थित कई सहकारी बैंकों पर नियामक मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए मौद्रिक दंड लगाया है। मुख्य कार्यवाही में सूरत पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 18.30 लाख रुपये का जुर्माना, प्राइम को-ऑपरेटिव बैंक पर 15 लाख रुपये का जुर्माना और सूरत जिला सहकारी बैंक लिमिटेड पर 14 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है, मुख्य रूप से सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग, ब्याज भुगतान और ऋण नियमों से संबंधित मुद्दों का हवाला देते हुए। सूरत पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (सितंबर 2025): बड़े ऋणों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को बड़े ऋणों की रिपोटिंग से संबंधित निर्देशों का पालन न करने पर 18.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। प्राइम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (अगस्त 2025): साइबर सुरक्षा नियंत्रणों का अनुपालन न करने और अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए सुविधाएं प्रदान करने में विफलता या देरी के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

कुप्रबंधन के लिए:-

सूरत के जिला रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सूरत जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मांडवी नागरिक सहकारी बैंक सूरत, पंचशील मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड सूरत, सूरत राष्ट्रीय सहकारी बैंक, सूरत पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्राइम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सूरत पर भारी जुर्माना लगाया गया है, जबकि बैंकों के बोर्डों को तत्काल भंग किया जाना चाहिए।

पश्चिम रेलवे द्वारा 19 मार्च, 2026 से 12-डिब्बों वाली 16 उपनगरीय सेवाओं का 15-डिब्बों में परिवर्तन

15-डिब्बों वाली सेवाओं की कुल संख्या बढ़कर होगी 227

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए वहन क्षमता बढ़ाने एवं अधिक सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से 19 मार्च, 2026 से 12-डिब्बों वाली मौजूदा 16 उपनगरीय सेवाओं को 15-डिब्बों वाली सेवाओं में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। इस विस्तार का उद्देश्य ट्रेनों की क्षमता में वृद्धि कर बढ़ती यात्री संख्या को समुचित रूप से समायोजित करना है। इससे ट्रेनों में भीड़भाड़ कम करने तथा दैनिक यात्रियों की सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन अतिरिक्त 15-डिब्बों वाली सेवाओं के शुरू होने के बाद उनकी कुल संख्या 211 से बढ़कर 227 हो जाएगी। हालांकि, उपनगरीय सेवाओं की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह 1414 ही रहेगी। बढ़ाई जा रही 16 सेवाओं में से 8 सेवाएं पीक आवर्स में (प्रातःकालीन पीक में 4 तथा सायंकालीन पीक में 4) परिचालित होंगी। यह पहल पश्चिम रेलवे की सुरक्षित, कुशल एवं यात्री-अनुकूल सेवाएं प्रदान करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे मुंबई की जीवनरेखा और अधिक सुदृढ़ होगी। विस्तृत सूची परिशिष्ट–I में संलग्न है।

रेल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि

जीएनएस)। वडोदरा मंडल द्वारा रेल अवसंरचना को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आनंद–गोधरा खंड के अंतर्गत लेवल क्रॉसिंग संख्या 54ए पर रिलीविंग गर्डर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

पश्चिम रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इंफ्रा का यह महत्वपूर्ण कार्य दिनांक 16 मार्च, 2026 को अप लाइन तथा 17 मार्च, 2026 को डाउन लाइन पर नियोजित 3 घंटे के ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान कुशलतापूर्वक संपन्न किया गया। कार्य के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया गया, जिससे यातायात संचालन पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा। उक्त अवसंरचना कार्य के निष्पादन में 500 टन क्षमता वाली अत्याधुनिक क्रेन का उपयोग किया गया, जिससे गर्डर लॉन्च अत्यंत सटीकता एवं सुरक्षित ढंग से किया जा सका। इस कार्य की समयबद्ध एवं सफल पूर्णता वडोदरा मंडल की तकनीकी दक्षता, सुनियोजित कार्यप्रणाली तथा प्रतिबद्धता का परिचायक है।

वडोदरा मंडल निरंतर रेल अवसंरचना के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रतिबद्ध है, जिससे यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं विश्वसनीय सेवाएं प्रदान की जा सकें।

सूरत: छात्रों के बीच बढ़ते अपराध और हथियारों से लैस गिरोह युद्ध, पुलिस की अक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत शिकागो की तरह बनता जा रहा है, क्योंकि पिछले छह महीनों से यहाँ लूटपाट, हत्या, बलात्कार, जबरन वसूली, सूदखोरों द्वारा उत्पीड़न और खुलेआम दादागिरी आदि की घटनाएं लगातार हो रही हैं। सवाल यह है कि पुलिस की कार्रवाई और डराने-धमकाने का काम कहाँ है?

सूरत शहर में हत्या, बलात्कार, जबरन वसूली, सूदखोरों द्वारा उत्पीड़न, लूटपाट, चोरी और मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। कुछ विशेष पुलिस थानों में भी ऐसी घटनाएं रोजाना घट रही हैं। डिंडोली, लिंबायत, गोदादरा, पांदेसरा, सचिन, सचिन जीआईडीसी, उधना आदि थानों में गंभीर अपराध दर्ज किए जाते हैं। सामान्य अपराधों का निपटारा थानों से ही कर दिया गया। और पुलिस रिकॉर्ड में अधिक अपराध दर्ज न करके अपराधों की संख्या कम दिखाई जा रही है।

इस प्रकार, पुलिस अधिकारी उच्च अधिकारियों को यह दिखाने के लिए झूठी छवि बनाते हैं कि उनके थाने में अपराध कम हुए हैं या अपराध दर घट गई है। जब हत्या, बलात्कार, जबरन वसूली, सूदखोरों को परेशान करना, डकैती जैसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार आरोपियों को घटनास्थल निरीक्षण के नाम पर अपराध स्थल पर ले जाया जाता है, तो पुलिस आरोपियों को लंगड़ाकर चलने की सलाह देती है ताकि वे तमाशा न करें और ऐसे अपराधियों को जनता के सामने प्रदर्शित न करें और यह न दिखाएं कि उन्होंने तृतीय श्रेणी की सजा अपनाई है। लेकिन उनके चेहरों को देखकर लगता है कि उन्हें पुलिस का कोई डर या खौफ नहीं है। पुलिस केवल यह दिखाती है कि उन्होंने किसी बड़े अपराधी को पकड़ा है। जब कोई गंभीर अपराध होता है, तो आरोपी दो-तीन दिन तक छिप जाते हैं। और जैसे ही जनता का गुस्सा शांत होता है, आरोपी अपने (पुलिस) सुरक्षाकर्मियों के साथ प्रकट होते हैं। या वे जगह दिखाते हैं ताकि पुलिस वहां जाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर ले और जनता को यह दिखाए कि उन्होंने खुद उन्हें गिरफ्तार किया है। इस दौरान, यानी जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जा रही होती है, तो आरोपियों को पुलिस पर हमला करते या हथियार से घायल करते हुए दिखाया जाता है, और पुलिस को आरोपियों के पैर में चोट पहुंचाते हुए दिखाया जाता है, यह कहते हुए कि उन्होंने पुलिस की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की थी। असल में, यह सब सिर्फ एक नाटक है।

आजकल छात्र कलम और पेंसिल रखने के बजाय ऑनलाइन चाकू और चॉपस्टिक मंगवाते हैं। और वे सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम इनका इस्तेमाल करने से नहीं डरते। पांदेसरा स्थित गैलेक्सी आर्मी इंटरनेशनल स्कूल में छात्रों के बीच हुई हालिया गैंगवार की घटना शिक्षा जगत, पुलिस और समाज के लिए शर्मनाक है। यदि छात्रों के माता-पिता या परिवार के पास लाइसेंसी हथियार हैं, तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ऐसे हथियार छोटे बच्चों के हाथों में न पड़ें।

जब 12 से 15 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चे ऐसे घातक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस का भय कहाँ है?

क्रूड ऑयल वायदा में 215 रुपये का ऊछाल: सोना वायदा 543 रुपये और चांदी वायदा 262 रुपये बढ़ा

जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 376064.28 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 25923.38 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 350140.55 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मार्च वायदा 38400 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 4305.33 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 16012.51 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा 156891 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 157580 रुपये और नीचे में 155739 रुपये पर पहुंचकर, 155736 रुपये के पिछले बंद के सामने 543 रुपये या 0.35 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 156279 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 347 रुपये या 0.27 फीसदी की बढ़त के साथ 127780 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 48 रुपये या 0.3 फीसदी की बढ़त के साथ 16029 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोना-मिनी अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 156606 रुपये के भाव पर खूलकर, 157600 रुपये के दिन के उच्च और 155750 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 555 रुपये या 0.36 फीसदी की बढ़त के साथ 156310 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 157497 रुपये के भाव पर खूलकर, 158175 रुपये के दिन के उच्च और 156528 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 156546 रुपये के पिछले बंद के सामने 554 रुपये या 0.35 फीसदी की बढ़त के साथ 157100 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सत्र के आरंभ में 261457 रुपये के भाव पर खूलकर, 262899 रुपये के दिन के उच्च और 254412 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 256532 रुपये के पिछले बंद के सामने 262 रुपये या 0.1 फीसदी की बढ़त के साथ 256794 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 90 रुपये या 0.03 फीसदी की तेजी के संग 262374 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-

कमोडिटी वायदाओं में 25923.38 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 350140.55 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 16012.51 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 38400 पॉइंट के स्तर पर

माइक्रो अप्रैल वायदा 115 रुपये या 0.04 फीसदी की बढ़त के साथ 262600 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। मेटल वर्ग में 2351.50 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा 4.55 रुपये या 0.39 फीसदी गिरकर 1176.8 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता मार्च वायदा 3.65 रुपये या 1.13 फीसदी लुढ़ककर 319.25 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 1.5 रुपये या 0.44 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 343.9 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मार्च वायदा 60 पैसे या 0.32 फीसदी के सुधार के साथ 187.35 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 7480.09 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 8845 रुपये के भाव पर खूलकर, 9106 रुपये के दिन के उच्च और 8811 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 215 रुपये या 2.47 फीसदी की तेजी के संग 8935 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 213 रुपये या 2.44 फीसदी की बढ़त के साथ 8934 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 280.6 रुपये के भाव पर खूलकर, 285.3 रुपये के दिन के उच्च और 279 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 279 रुपये के पिछले बंद के सामने 5.4 रुपये या 1.94 फीसदी की बढ़त के साथ 284.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 5.4 रुपये या 1.94 फीसदी बढ़कर 284.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 999 रुपये के भाव पर खूलकर, 40 पैसे या 0.04 फीसदी के सुधार के साथ 975.5 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 8952.07 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 7060.44 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1408.70 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 498.70 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 10.24 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 430.25 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 6094.79 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1360.43 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 6.41 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.78 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 11182 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 62830 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 31994 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 465840 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 65661 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7083 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 19889 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 76646 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 28653 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 31079 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मार्च वायदा 38370 पॉइंट पर खूलकर, 38400 के उच्च और 38365 के नीचले स्तर को छूकर, 127 पॉइंट बढ़कर 38400 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मार्च 9000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 10 रुपये की गिरावट के साथ 126 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.65 रुपये की बढ़त के साथ 14.05 रुपये हुआ।

सोना मार्च 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 77 रुपये की गिरावट के साथ 1040.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 270000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 684.5 रुपये की गिरावट के साथ 4821 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 44 पैसे की नरमी के साथ 8.75 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 325 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.82 रुपये की गिरावट के साथ 1.82 रुपये हुआ। पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मार्च 8900 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 227.8 रुपये की गिरावट के साथ 124.1 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.85 रुपये की गिरावट के साथ 10.6 रुपये हुआ।

सोना मार्च 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 214 रुपये की गिरावट के साथ 662 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 124 रुपये की गिरावट के साथ 582.5 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1150 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.1 रुपये की बढ़त के साथ 7.54 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.05 रुपये की बढ़त के साथ 4.3 रुपये हुआ।